International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्रामीण गरीबी : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रश्मि जोगी* डॉ. नीलम अग्रवाल ** डॉ. ए. के. पाण्डेय *** डॉ. ओमप्रकाश बघेल****

सार संक्षेप

सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश आज स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी एवं अशिक्षा जैसे गम्भीर समस्याओं से जूझ रही है। गरीबी से युवा शक्ति की ऊर्जा का विनाश हो रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाएं है पर युवाओं के पास रोजगार के अवसर नही है इसी कारण गरीबी एवं बेरोजगारी समाज के विकास के लिए अभिशाप बनती जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों में कमी, प्रदर्शन प्रभाव, औद्योगिक संघर्ष, जनसंख्या विस्फोट, लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन आदि प्रमुख कारक है जिससे देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है और विकास का पहिया रूक जाता है तथा ग्रामीण विकास की गति धीमी पड़ जाती है, इसलिए सरकार को ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जो कि पूरी तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गरीबी के दलदल से बाहर निकाले एवं कृषि को इतना अधिक विकसित करे कि ग्रामीण लोगों के पास गांव में ही रोजगार के व्यापक साधन व अवसर प्राप्त हो सके ताकि लोग शहरों की ओर काम की तलाश में भटके नही और न ही उन्हें पलायन करने की आवश्यकता पड़े।

शब्द कुंजी– गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास।

1. प्रस्तावना

वर्तमान युग आर्थिक विकास का युग है। आज पूरा विश्व आर्थिक विकास के लिए प्रयत्यनशील है। देश का तीव्र आर्थिक विकास भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक केन्द्रीय समस्या है साथ ही देश में गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएँ आर्थिक विकास की बड़ी चुनौती हैं। गरीबी की समस्या एक बहुआयामी समस्या है इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबी की गहनता शहरी गरीबी से अधिक होती है क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या गावों में निवासरत है जिनके पास रोजगार की समस्या बहुत अधिक होती है। न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर वाली कृषि के प्रारूप, पोषणीय जीवन निर्वाह की कमी, आय की कमी, कौशल की कमी आदि ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण है। वर्तमान में सरकार ने गरीबी रेखा को मापने के लिए सी. रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। सी.रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2009–10 में 38.2 प्रतिशत थी, जो 2011–12 में घटकर 29.5 प्रतिशत हो गयी अर्थात् गरीबी में 8.7 प्रतिशत की गिरावट आयी है। छत्तीसगढ़ में गरीबी 2009–10 में 53.8 प्रतिशत थी जो 2011–12 में घटकर 47.9 प्रतिशत हो गई। छत्तीसगढ़ में 2009–10 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 58.9 प्रतिशत थी, जो 2011–12 में घटकर 49.2 प्रतिशत हो गई तथा शहरी क्षेत्र में 2009–10 में 36.5 प्रतिशत थी जो 2011–12 में बढकर 43.7 प्रतिशत हो गई।

*शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
**सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुन्द (छ.ग.)
*** प्राध्यापक,अर्थशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
****सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय कुनकुरी,जशपुर (छ.ग.)

International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

2. अध्ययन का उद्देश्य

1. निदर्श परिवारों में गरीबी की स्थिति का अध्ययन करना ।

2.निदर्श परिवारों की गरीबी के कारणों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध प्रविधि

1. आंकड़ों का संकलन–प्रस्तावित अध्ययन प्राथमिक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंकों का सकंलन प्रत्यक्ष साक्षात्कर अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

2.शोध प्ररचना–अध्ययन के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले का चयन किया गया है। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति कैसी है ? कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है एवं इनकी उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करने के उद्देश्य से इस जिले का चयन किया गया। दुर्ग जिले में तीन विकासखण्ड दुर्ग, धमधा एवं पाटन है। उपर्युक्त तीनों विकासखण्डों के अंतर्गत ग्रामों की संख्या क्रमशः 80, 162 एवं 146 हैं। ग्रामों की संख्या को आनुपातिक तौर पर लिया गया है, ताकि ग्रामों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। आनुपातिक विधि के आधार पर दुर्ग विकासखण्ड से 02 ग्रामों का, धमधा विकासखण्ड से 04 ग्रामों का, पाटन विकासखण्ड से 03 ग्रामों का चयन किया गया। निदर्श ग्रामों का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर क्रमशः दुर्ग विकासखण्ड से कोड़िया तथा घुघसीडीह, धमधा विकासखण्ड से बोरसी, पथरिया, लिमतरा तथा भरनी एवं पाटन विकासखण्ड से छाटा, बठेना तथा सोनपुर ग्रामों को किया गया तथा स्लोविन निदर्शन विधि द्वारा न्यादर्श के आकार का चयन किया गया है, इस आधार पर चयनित निदर्श का आकार कुल 354 है। इन परिवारों में मुख्यतः सीमांत एवं लघु कृषक परिवार है।

3.आंकड़ों का विश्लेषण– संकलित प्राथमिक समंकों के विश्लेषण में आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

गरीबी की माप – गरीबी की माप करने के लिए सी. रंगराजन समीति के रिपोर्ट एवं हेड काउन्ट अनुपात का उपयोग किया गया है –

1.निदर्शपरिवारों में ग्रामीण गरीबी का मापन

सी. रंगराजन समीति के अनुसार (2014 की रिर्पोट)
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय =32 रू.
प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय =972 रू.
औसत 5 सदस्यों का प्रति परिवार मासिक उपभोग व्यय = 972 × 5 = 4860 रू .
निदर्श परिवारों में औसत परिवार सदस्यों की संख्या 6 है = 972 × 6 = 5832 रू.प्रति परिवार मासिक उपभोग व्यय

2.हेड काउन्ट अनुपात :– यह अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के अनुपात का मापता है।

$$HP = n / N$$

HP = हेड काउन्ट अनुपात
n = गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगो की संख्या
N = कुल जनसंख्या

4. अध्ययन का विश्लेषण

1.परिवारों का वर्गीकरण

सारणी क्रमांक 1.1
निदर्श परिवारों में कृषकों का प्रकार

विकासखण्ड	कृषकों का प्रकार		
	सीमांत कृषक	लघु कृषक	कुल
दुर्ग	52 (24.2)	40 (28.8)	92 (26.0)
धमधा	91 (42.3)	55 (39.6)	146 (41.2)
पाटन	72 (33.5)	44 (31.6)	116 (32.8)
कुल	215 (100)	139 (100)	354 (100)

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण । नोट – कोष्ठक में दी गयी संख्या प्रतिशत में है।

सारणी क्रमांक 1.1 में निदर्श परिवार में कृषकों के प्रकार के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि निदर्श परिवारों में कृषक परिवारों की कुल संख्या 354 है जिसके अंतर्गत दुर्ग, धमधा व पाटन तीनों विकासखण्ड में कृषक परिवारों की कुल संख्या क्रमशः 92, 146 व 116 है। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि निदर्श परिवार में सीमांत कृषक परिवारों की कुल संख्या 215 है जिसके अंतर्गत दुर्ग, धमधा व पाटन तीनों विकासखण्ड में सीमांत कृषक परिवारों की संख्या क्रमशः 52 (24.2 प्रतिशत), 91(42.3 प्रतिशत) व 72 (33.5 प्रतिशत) है तथा निदर्श परिवार में लघु कृषक परिवारों की कुल संख्या 139 है जिसके अंतर्गत दुर्ग, धमधा व पाटन तीनों विकासखण्ड में लघु कृषक परिवारों की संख्या क्रमशः 40 (28.8 प्रतिशत), 55 (39.6 प्रतिशत) व 44 (31.6 प्रतिशत) है।

International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

2. गरीबी की स्थिति का विश्लेषण

सारणी क्रमांक 1.2
निदर्श परिवारों की निर्धनता की स्थिति का अध्ययन

विकासखंड	बी. पी. एल. परिवार			ए.पी.एल. परिवार की संख्या	कुल
	संख्या	सदस्यों की संख्या	परिवार का आकार		
दुर्ग	18	114	6.3	74	92
धमधा	35	254	7.2	111	146
पाटन	43	282	6.5	73	116
कुल	96	650	6.7	258	354

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण ।

सारणी क्रमांक 1.2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि निदर्श परिवारों की गरीबी की स्थिति को सी. रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति परिवार मासिक उपभोग व्यय के आधार पर विश्लेषण किया गया है। निदर्श परिवारों की कुल संख्या 354 है जिसमें प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 972 रूपये से कम व्यय करने वाले बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की संख्या 96 है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 972 रूपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से अधिक व्यय करने वाले परिवारों को ए.पी. एल. (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवार कहते हैं जिनकी संख्या कुल 258 है। पाटन विकासखंड मे बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 43, सदस्यों की संख्या 282 तथा परिवार का आकार 6.5 है। धमधा विकासखंड में बी.पी. एल. परिवारों की संख्या 35, सदस्यों की संख्या 254 व परिवार का आकार 7.2 है। दुर्ग विकासखंड में बी.पी. एल. परिवारों की संख्या 18, सदस्यों की संख्या 114 तथा परिवार का आकार 6.3 है इस प्रकार स्पष्ट है कि पाटन विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अन्य विकासखंडों की तुलना में अधिक है तथा दुर्ग विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अन्य विकासखंडों की तुलना में सबसे कम है अर्थात् पाटन विकासखंड की अपेक्षा दुर्ग विकासखंड में गरीबों का प्रतिशत कम है क्योंकि दुर्ग विकासखंड अधिक सिंचित है जिसके कारण यहां कृषि उत्पादकता, भूमि का आकार एवं रोजगार की सुविधा पाटन विकासखंड की अपेक्षा अधिक है।

International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सारणी क्रमांक 1.3

निदर्श परिवारों में हेड काउन्ट अनुपात

जिला	बी. पी. एल. परिवार में सदस्यों की संख्या	हेड काउन्ट अनुपात
दुर्ग	114	0.21
धमधा	254	0.29
पाटन	282	0.40
कुल	650	0.30

स्त्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण ।

सारणी क्रमांक 1.3 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि चयनित कुल निदर्श ग्रामों में हेड काउन्ट अनुपात पर आधारित गरीबी 0.30 है जो यह बताती है कि चयनित कुल निदर्श ग्रामों में 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पाटन विकासखंड मे हेड काउन्ट अनुपात 0.40 प्रतिशत अर्थात् 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा धमधा एवं दुर्ग विकासखंड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लागों का हेड काउन्ट अनुपात क्रमशः 0.29 (29 प्रतिशत) व 0.21 (21 प्रतिशत) है अर्थात् पाटन विकासखंड में गरीबी का अनुपात अन्य विकासखंडों की तुलना में अधिक है तथा दुर्ग विकासखंड में गरीबी का अनुपात अन्य विकासखंडों की तुलना में सबसे कम है क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति मासिक आय अधिक है।

निष्कर्ष

1 .निदर्श परिवारों में सीमांत कृषक परिवारों की संख्या कुल 215 है जिसके अंतर्गत दुर्ग, धमधा व पाटन तीनों विकासखण्ड में सीमांत कृषक परिवारों की संख्या क्रमशः 52 (24.2 प्रतिशत), 91(42.3 प्रतिशत) व 72 (33.5 प्रतिशत) है तथा निदर्श परिवार में लघु कृषक परिवारों की संख्या कुल 139 है जिसके अंतर्गत दुर्ग, धमधा व पाटन तीनों विकासखण्ड में लघु कृषक परिवारों की संख्या क्रमशः 40 (28.8 प्रतिशत), 55 (39.6 प्रतिशत) व 44 (31.6 प्रतिशत) है।

2. पाटन विकासखंड मे बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 43, धमधा विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 35 एवं दुर्ग विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 18 है इस प्रकार स्पष्ट है कि पाटन विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अन्य विकासखंडों की तुलना में अधिक है तथा दुर्ग विकासखंड में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अन्य विकासखंडों की तुलना में सबसे कम है क्योंकि दुर्ग विकासखंड अधिक सिंचित है

जिसके कारण यहां कृषि उत्पादकता, भूमि का आकार एवं रोजगार की सुविधा पाटन विकासखंड की अपेक्षा अधिक है।

3. कुल निदर्श ग्रामों में 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पाटन विकासखंड मे हेड काउन्ट अनुपात 0.40 प्रतिशत अर्थात् 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा धमधा एवं दुर्ग विकासखंड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लागों का हेड काउन्ट अनुपात क्रमशः 0.29 (29 प्रतिशत) व 0.21 (21 प्रतिशत) है अर्थात् पाटन विकासखंड में गरीबी का अनुपात अन्य विकासखंडों की तुलना में अधिक है तथा दुर्ग विकासखंड में गरीबी का अनुपात अन्य विकासखंडों की तुलना में सबसे कम है क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति मासिक आय अधिक है।

सुझाव

1. **युवाओं एवं किसानों को कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करना** –वर्तमान समय में लोग जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं कृषि कार्य करना पसंद नही करते हैं। जबकि सभी शिक्षित लोगों को रोजगार देना सरकार के लिए संभंव नही है इसलिए सरकार को चाहिए कि युवा पीढ़ी को आधुनिक कृषि के महत्व के बारे में बतायें कि वह स्वयं ही कृषि से अपना स्वयं का व्यावसाय स्थापित कर आय प्राप्त कर सकता है तथा सरकार द्वारा युवाओं एवं किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य, कम ब्याज पर ऋण, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था एवं कम दर में प्रमाणित बीज प्रदान कर उन्हें कृषि कार्य करने के लिए आकर्षित एवं प्रोत्साहित करें।

2. श्रम बल –देश में अधिकांश आबादी गांवों में रहते हैं और गांव में ज्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं इसलिए सरकार को श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र पर जोर देना चाहिए ताकि श्रमिकों को कृषि से उच्च उत्पादकता के क्षेत्रों में स्थानान्तिरत किया जा सके।

3. कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा – ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कृषक परिवार अशिक्षित होते हैं जिसके कारण कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा नही मिलता और वे कृषि कार्य के लिए वही पुरानी तकनीक एवं पुराने बीजों का उपयोग करते हैं। जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता कमी होताी है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं प्रसंस्करणों का प्रशिक्षण देकर उसे उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिल सकेगा।

4. सिंचाई व्यवस्था –ग्रामीण क्षेत्र में सीमांत एवं लघु कृषको के सामनें सिंचाई व्यवस्था के अभाव में केवल एक फसलीय अनाज उत्पादन कर पाते हैं जिससे बाकी समय उन्हें कोई कार्य नही मिलने के कारण वे बेरोजगार होते हैं, इसलिए उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए उचित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अनेक फसलों का उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

5. कृषि के सहायक क्षेत्रों का विकास – कृषि के सहायक क्षेत्रों जैसे– मुर्गीपालन, मछलीपालन, पशुपालन आदि का भी विकास करना चाहिए इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

संदर्भग्रंथ सूची

1. Datt Gourav (1999)," Has Poverty Declined Since Ecnomic Reforms?" Economic and Political Weekly December 11 vol 34.PP.3516-3518.

2. Dev S. Mahendra and Ranade Ajit (1998), "Rising food Prices and Rural Poverty Going Beyond Correlations", Economic and Political Weekly, September 26 PP.2529-2535.

3. Ghosh Madhusudan (2012), " Micro-Finance and Rural Poverty In India" SHG- Bank Linkage Programme Journal of Rural Development Vol.31 No. 3 PP.347- 363.

4. Himanshu (2007), "Recent Trends in Poverty and Inequality: Some Preliminary Results" Economic and Political Weekly, February 10, PP.497-508.

5. Kumar Anjani, Kumar Praduman and Sharma Alakh N. (2011), "Rural Poverty and Agricultural Growth in India: Implications for the Twelfth five Year Plan", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol 66 No.3 July-Sept. PP. 369-277.